and SCICI being non-governmental companies, their operations are managed and supervised by their respective Boards. Where financial institutions are statutory in character, supervisory responsibilities are in accordance with the Acts under which they are established.

Autonomy of Management in SBI

2616. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Financial Express of 30th July, 1993 captioned "SBI seeks autonomy of management" flexibility to have recruitment procedures, remuneration packages, career progressive plan and placement policy which conform to charging market practices conditions and customer requirements swiftly;

(b) whether it is a fact that SIBs Chairman Mr. D. Basu has urged the Central Government to look into the above reported issues urgently and allow managements of public sector banks appropriate autonomy in these areas so that they could compete effectively with private sectod and international banks and free them from bureaucratic procedures; and

(c) if so, what is the reaction of Government of India thereto and particularly to the proposal of appointment of a State Bank Lokpal to perform the functions of an ombudsman?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) ot (c) The information is being collected from the bank and, to the extent available will be laid on the Table of the Houe.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2617. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कलकत्ता और इन्दौर शाखाओं में घोटाले और अनियमितताओं के लिए कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या-क्या है ;

(ग) क्या प्रबन्ध मंडल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध कब मुकदमें दायर किए जाएंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इज्राइली उद्योगपतियों द्वारा भारत में निवेश की इच्छा प्रकट करना

2618. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्राइल के कुछ उद्योगपतियों ने भारत में विद्युत, कृषि और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाया है ;